भूपेंद्र

बनाम

महाराष्ट्र राज्य और अन्य

(आपराधिक अपील सं.890/2008)

14 मई, 2008

(डॉ. अरिजीत पासायत और पी. सतशिवम, जे. जे.)

महाराष्ट्र स्लम-लॉर्ड्स, बूटलेगर्स, ड्रग्स ऑफेंडर्स एंड डेंजरस पर्सन्स की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1981।3(2) और 8 (2)-अधिनियम के तहत निरोध आदेश-निरोध की गतिविधियों और निरोध आदेश की तारीख के बीच संबंध की अनुपस्थिति में के आधार पर चुनौती-आयोजितःनिरोध को सशक्त बनाने का प्रावधान प्रस्तावित बचाव की आदतन गतिविधियों से संबंधित है-इसलिए, ऐसे उदाहरण हैं जो तत्काल निकटता के नहीं हो सकते हैं, लेकिन उस पैटर्न का संकेत दे सकते हैं-तथ्यों पर, निरोध आदेश से पता चलता है कि हिंसक अपराधों के लिए असामाजिक तत्वों द्वारा भुगतान पर डेफ्टेनु को काम पर रखा गया था-लाइव लिंक की अनुपस्थिति में के निष्कर्ष के लिए दूरस्थ अतीत की घटना नहीं-इस प्रकार, निरोध आदेश सही है।

निवारक निरोधः

निवारक निरोध का कानून-चर्चा की गई।

निरोध आदेश-सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल कार्य-सुधार और व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के क्षेत्र '-के बीच अंतर।

शब्द और वाक्यांशः कानून और व्यवस्था ',' सार्वजनिक व्यवस्था 'और-' राज्य की सुरक्षा 'का अर्थ।

अपीलकर्ता यू/एस के खिलाफ निरोध आदेश पारित किया गया था। 3(2) महाराष्ट्र स्लमलॉर्ड, बूटलेगर्स, ड्रग अपराधियों की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम और खतरनाक व्यक्ति अधिनियम, 1981 उन्हें अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था। नजरबंदी के आधार 23.4.07 पर दिए गए थे। अपीलकर्ता ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की और निरोध आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि निरोध आदेश कानून और व्यवस्था की स्थिति से संबंधित मामलों का संकेत देता है और इसका सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव से कोई लेना-देना नहीं है और ये पुराने थे। उच्च न्यायालय ने पाया कि कई अपराध 2005 से निरोध आदेश से कुछ दिन पहले तक पंजीकृत थे और निरोध की गतिविधियों और निरोध आदेश पारित करने की तारीख के बीच सीधा संबंध था। उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।इसलिए वर्तमान अपील।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि बंदी की गतिविधियों और निरोध के विवादित आदेश के पारित होने की तारीख के बीच कोई सीधा संबंध नहीं था; वह संदर्भ कुछ घटनाओं के लिए किया गया था जो कथित रूप से 2005 में हुई थीं और किसी भी घटना में जब निवारक कार्रवाई के संदर्भ में धारा 107 और धारा 110 सीआर.पी.सी. ले लिया गया था, हिरासत का आदेश पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी; कि कथित कार्य इस प्रकार हैंःकानून और व्यवस्था की स्थिति से सबसे अधिक संबंधित और सार्वजनिक व्यवस्था से कोई लेना-देना नहीं होना; कि इन कैमरा गवाहों के बयान पर हिरासत में लिए गए प्राधिकारी द्वारा इस राय के बिना भरोसा नहीं किया जाना चाहिए था कि क्या वे सच्चाई का प्रतिनिधित्व आदेशते हैं।

प्रतिवादी-राज्य और उसके अधिकारियों ने तर्क दिया कि निरोध आदेश सही था।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1.1. निरोध के आदेश से पता चलता है कि अपीलकर्ता को अक्सर हिंसक

अपराधों के लिए असामाजिक तत्वों द्वारा भुगतान पर काम पर रखा जाता है।बंदी और उसके सहयोगियों के पास हमेशा घातक हथियार होते थे और जिन उदाहरणों पर प्रकाश डाला जाता था वे 1.5.2005,1.6.2005 और 24.2.2006 से संबंधित थे और एक विशेष समुदाय और बिल्डरों के बीच भूमि के कब्जे और बंदी की गतिविधियों को लेकर विवाद था, और अंत में 24.3.2007 पर यह ध्यान दिया गया है कि एक विशेष हाई स्कूल के मैदान में गंभीर दंगे की स्थिति विकसित हुई थी जहां एक विशेष समुदाय के सैकड़ों सदस्य एकत्र हुए थे। इसके परिणामस्वरूप नजरबंदी की गतिविधियों के कारण तीव्र भय और दहशत की स्थिति पैदा हो गई। निरोध के आदेश में यह भी बताया गया था कि धारा 107 और 110 के तहत की गई विभिन्न निवारक कार्रवाई का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला और बंदी ने अपनी हिंसक और आपराधिक गतिविधियों को जारी रखा।जिन गवाहों से कैमरे में पूछताछ की गई, उनका भी उल्लेख किया गया।जहाँ तक इन गवाहों की सच्चाई का संबंध है, एस का संदर्भ दिया गया था।8(2) अधिनियम जो जनहित में कुछ गवाहों के बयान को रोकने की अनुमति देता है।[पैरा 6] [714 एफ, जी 715-ए, बी]

1.2. लाइव लिंक के सवाल के संबंध में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हिरासत को सशक्त बनाने का प्रावधान प्रस्तावित बंदी की आदतन गतिविधियों से संबंधित है। इसलिए, ऐसा उदाहरण होना चाहिए जो तत्काल निकटता का न हो, लेकिन उस पैटर्न को इंगित कर सकता है। उदाहरण के मामले में, लाइव लिंक की अनुपस्थिति में के निष्कर्ष की गारंटी देने के लिए घटना को दूरस्थ अतीत नहीं कहा जा सकता है। [पैरा 14] [718-बी, सी]

कानू विश्वास अन्य पश्चिम बंगाल राज्य ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 1656; डॉ. राम मनोहर लोहिया अन्य बिहार राज्य और अन्य 1966 (1) एस. सी. आर. 70; किशोरी मोहन बेरा अन्य पश्चिम बंगाल राज्य 1972 (3) एस. सी. सी. 845; पुष्कर मुखर्जी अन्य पश्चिम बंगाल राज्य 1969 (2) एस. सी. आर. 635; अरुण घोष अन्य

पश्चिम बंगाल राज्य 1970 (3) एस. सी. आर. 288; नागेंद्र नाथ मंडल अन्य पश्चिम बंगाल राज्य 1972 (1) एस. सी. सी. 498; बाबुल मित्रा उपनाम अनिल मित्रा अन्य पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य 1973 (1) एस. सी. सी. 393, मिलन बनिक अन्य पश्चिम बंगाल राज्य 1974 (4) एस. सी. सी. 504; कुसो साह अन्य बिहार राज्य और Ors.1974 (1) एस. सी. सी. 185; गुरप्रीत कौर अन्य पश्चिम बंगाल राज्य।

महाराष्ट्र राज्य 1992 (2) एस. सी. सी. 177; टी. के. गोपाल बनाम कर्नाटक राज्य 2000 (6) एस. सी. सी. 168; महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद।याकूब 1980 (2) एस. सी. आर. 1158 और पुलिस आयुक्त बनाम सी.अनीता 2004 (7) एस. सी. सी. 467-पर भरोसा किया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्र अधिकार दाण्डिक अपीलीय सं 890/2008

बॉम्बे उच्च न्यायालय औरंगाबाद पीठ के आपराधिक डब्ल्यू. पी. संख्या 372/2007 के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 14.9.2007 से,

अपीलकर्ता के लिए अनंतभूषण कनाडे, आर. के. गुप्ता और अरिबम गुणेश्वर शर्मा।

प्रतिवादीओं के लिए शेखर नेफडे, रवींद्र केशवराव विज्ञापन।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे.

1. अवकाश अनुदत्त गई।

2. इस अपील में चुनौती बॉम्बे उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के उस फैसले को दी गई है जिसमें एक भूपेंद्र द्वारा भारत के संविधान, 1950 (संक्षेप में 'संविधान') के अनुच्छेद 226 के तहत दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया गया था। बाद में 'डिटेनु' के रूप में संदर्भित)

3. रिट याचिका में प्रार्थना जिला मजिस्ट्रेट, अहमदनगर द्वारा दिनांकित 23.4.2007 द्वारा पारित निर्णय और आदेश और महाराष्ट्र सरकार के अवर सचिव, गृह विभाग (विशेष) द्वारा दिनांकित 12.6.2007 आदेश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द करने और रद्द करने की थी।महाराष्ट्र स्लमलोड्र्स, बूटलेगर्स, ड्रग ऑफेंडर्स एंड डेंजरस पर्सन्स एक्ट, 1981 (संक्षेप में 'एक्ट') की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम की खंड 3 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के कथित प्रयोग में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा निरोध का आदेश पारित किया गया था।हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने अधिनियम के तहत हिरासत में लिया। नजरबंदी के आधार 23.4.2007 पर दिए गए थे।बंदी के कई कृत्यों को उजागर किया गया था जो हिरासत में लेने वाले अधिकारी के अनुसार हिरासत में रखने की आवश्यकता थी।

अपीलकर्ता ने मुख्य रूप से यह रुख अपनाया कि निरोध का आदेश कानून और व्यवस्था की स्थिति से संबंधित मामलों को इंगित करता है और इसका सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव से कोई लेना-देना नहीं है और निरोध के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक माने जाने वाले पुराने हैं। यह प्रस्तुत किया गया था कि यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि बंदी के कथित कृत्यों ने जीवन की गति को बाधित किया। उच्च न्यायालय को कोई सार नहीं मिला और कहा कि कई अपराध 2005 से कुछ दिनों तकनिरोध के आदेश से पहले दर्ज किए गए थे। बंदी के खिलाफ की गई निवारक कार्रवाई अप्रभावी साबित हुई, उसे विभिन्न तिथियों पर बांड निष्पादित करने के लिए कहा गया था, लेकिन तीन साल की अवधि के लिए अच्छे व्यवहार के लिए बांड निष्पादित करने के बाद भी, बंदी ने बांड की शर्तों का उल्लंघन किया और कारण बताए जाने का नोटिस जारी किया गया। कैमरे के बयान में गवाहों का संदर्भ 24.3.2001 की एक घटना के लिए दिया गया था और अतीत में हिरासत में लिए गए व्यक्ति की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए हिरासत में लिए गए व्यक्ति की गतिविधियों और उसके विवादित आदेश के पारित होने की तारीख के बीच एक सीधा संबंध था।

यह अवलोकन बंदी के इस रुख के कारण किया गया कि कोई लाइव लिंक नहीं था। अंत में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी गई। अपील के समर्थन में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि कोई लाइव लिंक नहीं था।कुछ घटनाओं का संदर्भ दिया गया था जो कथित रूप से 2005 में की गई थीं और किसी भी घटना में जब संहिता की खंड 107 के संदर्भ में निवारक कार्रवाई की गई थी। दंड प्रक्रिया, 1973 (संक्षेप में 'सीआर.पी.सी..') और खंड 110 सीआर.पी.सी. को लिया गया है, हिरासत का आदेश पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।यह भी बताया गया कि कथित कृत्य सबसे अधिक कानून और आदेश की स्थिति से संबंधित हैं और इनका सार्वजनिक आदेश से कोई लेना-देना नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि इन कैमरा गवाहों के बयान पर हिरासत में लिए गए प्राधिकारी द्वारा इस राय के बिना भरोसा नहीं किया जाना चाहिए था कि क्या वे सच्चाई का प्रतिनिधित्व करते हैं।

5. दूसरी ओर प्रतिवादी-राज्य और उसके कार्यकर्ताओं के विद्वान वकील ने निरोध के आदेश का समर्थन किया।

6. निरोध के आदेश से पता चलता है कि अपीलकर्ता को अक्सर हिंसक अपराधों के लिए असामाजिक तत्वों द्वारा भुगतान पर काम पर रखा जाता है। बंदी और उसके सहयोगियों के पास हमेशा घातक हथियार होते थे और 1.5.2005, 1.6.2005 और 24.2.2006 से संबंधित उदाहरण और एक विशेष समुदाय और बिल्डरों के बीच विवाद को हिरासत के उद्देश्य से प्रासंगिक माना जाता था। यह प्रस्तुत किया गया था कि यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि बंदी के कथित कृत्यों ने जीवन की गति को बाधित किया। उच्च न्यायालय को कोई सार नहीं मिला और कहा कि कई अपराध 2005 से हिरासत के आदेश से कुछ दिन पहले तक दर्ज किए गए थे।बंदी के खिलाफ की गई निवारक कार्रवाई अप्रभावी साबित हुई, उसे विभिन्न तिथियों पर बांड निष्पादित करने के लिए कहा गया था, लेकिन तीन साल की अवधि के लिए अच्छे व्यवहार के लिए बांड निष्पादित करने के बाद भी, बंदी ने बांड की शर्तों का उल्लंघन किया और

कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया।कैमरे के बयान में गवाहों का संदर्भ 24.3.2001 की एक घटना के लिए दिया गया था और अतीत में हिरासत में लिए गए व्यक्ति की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए हिरासत में लिए गए व्यक्ति की गतिविधियों और हिरासत के विवादित आदेश के पारित होने की तारीख के बीच एक सीधा संबंध था। यह अवलोकन बंदी के इस रुख के कारण किया गया कि कोई लाइव लिंक नहीं था। अंततः बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी गई,

अपील के समर्थन में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि कोई लाइव लिंक नहीं था। 2005 में कथित रूप से की गई कुछ घटनाओं का संदर्भ दिया गया था और किसी भी घटना में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की खंड 107 (संक्षेप में 'दंड प्रक्रिया संहिता') के संदर्भ में निवारक कार्रवाई की गई थी। सीआरपी. सी. ') और खंड 110. सीआरपी. सी. ले लिया गया है, हिरासत का आदेश पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।यह भी बताया गया कि कथित कृत्य-सबसे अधिक कानून और आदेश की स्थिति से संबंधित हैं और इनका सार्वजनिक आदेश से कोई लेना-देना नहीं है। यह आगे कहा गया कि कैमरे में कैद गवाहों के बयान पर हिरासत में लिए गए प्राधिकारी द्वारा इस राय के बिना भरोसा नहीं किया जाना चाहिए था कि क्या वे सच्चाई का प्रतिनिधित्व करते हैं।

5. दूसरी ओर प्रतिवादी-राज्य और टी. टी. एस. कार्यकर्ताओं के विद्वान वकील ने निरोध के आदेश का समर्थन किया।

6. निरोध के आदेश से पता चलता है कि अपीलकर्ता को अक्सर हिंसक अपराधों के लिए असामाजिक तत्वों द्वारा भुगतान पर काम पर रखा जाता है। बंदी और उसके सहयोगियों के पास हमेशा घातक हथियार होते थे और 1.5.2005,1.6.2005 और 24.2.2006 से संबंधित उदाहरण और एक विशेष समुदाय और बिल्डरों के बीच भूमि के कब्जे और डीएनयू की गतिविधियों को लेकर विवाद, और अंत में 24.3.2007 पर

यह नोट किया गया है कि एक समय में गंभीर दंगाई स्थिति विकसित हुई। विशेष रूप से उच्च विद्यालय का मैदान जहां एक विशेष समुदाय के सैकड़ों सदस्य एकत्र होते हैं। इसके परिणामस्वरूप नजरबंदी की गतिविधियों के कारण तीव्र भय और दहशत की स्थिति पैदा हो गई। निरोध के आदेश में यह भी बताया गया कि धारा 107 और 110 सीआर.पी. सी. के तहत विभिन्न निवारक कार्रवाई की गई है। कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला और बंदी ने अपनी हिंसक और आपराधिक गतिविधियों को जारी रखा।जिन गवाहों से पूछताछ की गई, उनका भी उल्लेख किया गया।कैमरा।जहाँ तक इन गवाहों की सच्चाई का संबंध है, अधिनियम की खंड 8 (2) का संदर्भ दिया गया था जो कुछ गवाहों के बयान को जनहित में गवाह रोकने की अनुमति देता है।

7. महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्या बंदी की गतिविधियाँ सार्वजनिक आदेश के लिए प्रतिकूल थीं। जबकि 'कानून और व्यवस्था' अभिव्यक्ति का दायरा व्यापक है क्योंकि कानून का उल्लंघन हमेशा व्यवस्था को प्रभावित आदेशता है।'' सार्वजनिक व्यवस्था' का दायरा संकुचित है, और सार्वजनिक व्यवस्था केवल ऐसे उल्लंघन से प्रभावित हो सकती है जो समुदाय या बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित आदेशता है। सार्वजनिक आदेश समुदाय के जीवन की सम गति है जो देश को पूरे या एक निर्दिष्ट इलाके के रूप में ले जाती है।' कानून और व्यवस्था' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' के क्षेत्रों के बीच का अंतर समाज पर विचाराधीन अधिनियम की पहुंच की डिग्री और सीमा में से एक है। यह अधिनियम समुदाय के जीवन की गति को बाधित आदेशने की क्षमता रखता है जो इसे सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल बनाता है।यदि इसके प्रभाव में कोई उल्लंघन केवल कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित है जो सीधे तौर पर जनता के एक व्यापक स्पेक्ट्रम से अलग के रूप में शामिल हैं, तो यह केवल कानून और आदेश की समस्या को उठा सकता है। यह अव्यवस्था के एक विशेष विस्फोट से मुक्त आतंक की लहर की लंबाई, परिमाण और तीव्रता है जो इसे 'कानून और व्यवस्था' से संबंधित 'सार्वजनिक व्यवस्था' को प्रभावित करने वाले कार्य के रूप में अलग करने

में मदद करती है। पूछने के लिए प्रश्न हैंः क्या यह समुदाय के वर्तमान जीवन में अशांति का कारण बनता है ताकि सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी हो या क्या यह केवल एक व्यक्ति को प्रभावित आदेशता है जिससे समाज की शांति बाधित नहीं होती है?" इस सवाल का सामना हर मामले में इसके तथ्यों पर किया जाना चाहिए।

8. "सार्वजनिक आदेश "जिसे फ्रांसीसी 'ऑर्ड्रे पब्लिक' कहते हैं और कानून और आदेश के सामान्य रखरखाव से कुछ अधिक है।यह निर्धारित आदेशने के लिए अपनाया जाने वाला परीक्षण कि क्या कोई अधिनियम कानून और व्यवस्था या सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित आदेशता है, यह हैःक्या यह समुदाय के वर्तमान जीवन में अशांति पैदा आदेशता है ताकि सार्वजनिक व्यवस्था में अशांति पैदा हो या क्या यह केवल एक व्यक्ति को प्रभावित आदेशता है जिससे समाज की शांति बाधित नहीं होती है?(कानू विश्वास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 1656) देखें।

9. "'सार्वजनिक व्यवस्था' सार्वजनिक सुरक्षा और शांति का पर्याय हैंः यह राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली क्रांति, नागरिक संघर्ष, युद्ध जैसी राष्ट्रीय उथल-पुथल के विपरीत स्थानीय महत्व के उल्लंघनों से जुड़ी अव्यवस्था की अनुपस्थिति में है। यदि सार्वजनिक आदेश बाधित होती है, तो सार्वजनिक अआदेश पैदा होनी चाहिए। शांति के हर भंग से सार्वजनिक अव्यवस्था नहीं होती है। जब दो शराबी झगड़ते हैं और झगड़ते हैं तो आदेश होती है, लेकिन सार्वजनिक अआदेश नहीं होती। उनसे कानून और आदेश बनाए रखने की शक्तियों के तहत निपटा जा सकता है लेकिन इस आधार पर हिरासत में नहीं लिया जा सकता है कि वे सार्वजनिक आदेश को बिगाड़ रहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रखरखाव से अव्यवस्था को रोका जा सकता है लेकिन विकार एक व्यापक वर्ण आदेश है, जिसमें एक छोर पर छोटी गड़बड़ी और दूसरे पर सबसे गंभीर और विनाशकारी घटनाएं शामिल हैं।(डॉ. राम मनोहर लोहिया अन्य बिहार राज्य और अन्य देखें। (1966 (1) एससीआर

10. 'लोक व्यवस्था ',' कानून और व्यवस्था 'और' राज्य की सुरक्षा 'काल्पनिक रूप से तीन संकेंद्रित वृत्तों को आआदेशित आदेशते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा कानून और व्यवस्था का प्रतिनिधित्व आदेशता है, अगला सार्वजनिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व आदेशता है और सबसे छोटा राज्य की सुरक्षा का प्रतिनिधित्व आदेशता है।कानून के प्रत्येक उल्लंघन से व्यवस्था प्रभावित होनी चाहिए, लेकिन कानून को प्रभावित आदेशने वाला कार्य होना चाहिए। और व्यवस्था आवश्यक रूप से सार्वजनिक व्यवस्था को भी प्रभावित नहीं आदेश सकती है। समान रूप से, एक अधिनियम सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित आदेश सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि राज्य की सुरक्षा को प्रभावित आदेशे। सच्चा परीक्षण उस प्रकार का नहीं है, बल्कि विचाराधीन कार्य की क्षमता है।एक कार्य केवल व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है जबकि दूसरे का, हालांकि एक समान प्रकार का, ऐसा प्रभाव हो सकता है कि यह समुदाय के जीवन की गति को बाधित करेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई अतिव्यापी नहीं हो सकता है, इस अर्थ में कि कोई कार्य एक ही समय में दो अवधारणाओं के अंतर्गत नहीं आ सकता है। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित आदेशने वाले किसी अधिनियम का प्रभाव हो सकता है कि यह सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा दोनों को प्रभावित करेगा। [किशोर मोहन बेरा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1972 (3) एस. सी. सी. 845); पुष्कर मुखर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1969 (2) एस. सी. आर. 635); अरुण घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1970 (3) एस. सी. आर. 288); नागेंद्र नाथ मंडल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1972 (1) एस. सी. सी. 498) देखें।

11. अरुण घोष के मामले (ऊपर) में 'कानून और व्यवस्था' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' के बीच के अंतर को संक्षेप में बताया गया है। उस निर्णय के अनुसार 'कानून और व्यवस्था' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' के क्षेत्रों के बीच सही अंतर "समाज पर विचाराधीन अधिनियम की पहुंच की डिग्री और सीमा" है। न्यायालय ने कहा कि "अधिनियम अपने आप में अपनी गंभीरता का निर्धारक नहीं है। इसकी गुणवत्ता में

अंतर नहीं हो सकता है लेकिन इसकी क्षमता में यह बहुत अलग हो सकता है।(बाबुल मित्रा उपनाम अनिल मित्रा अन्य पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य देखें। (1973 (1) एस. सी. सी. 393, मिलन बनिक अन्य पश्चिम बंगाल राज्य (1974 (4) एस. सी. सी. 504)।

12. कानून और आदेश और सार्वजनिक आदेश के क्षेत्रों के बीच वास्तविक अंतर केवल अधिनियम की प्रकृति या गुणवत्ता में नहीं है, बल्कि समाज पर इसकी पहुंच की मात्रा और विस्तार में भी है। प्रकृति में समान, लेकिन विभिन्न संदर्भों और परिस्थितियों में किए गए कार्य, अलग-अलग प्रतिक्रियाओं का कारण बन सकते हैं। एक मामले में यह केवल विशिष्ट व्यक्तियों को प्रभावित आदेश सकता है, और इसलिए केवल कानून और व्यवस्था की समस्या को छूता है, जबकि दूसरे में यह सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित आदेश सकता है। अतः यह क्रिया अपने आप में अपने गुरुत्वाकर्षण का निर्धारक नहीं है। अपनी गुणवत्ता में यह अन्य समान कार्यों से अलग नहीं हो सकता है, लेकिन इसकी क्षमता में, यानी समाज पर इसके प्रभाव में, यह बहुत अलग हो सकता है।

13. दोनों अवधारणाओं में अच्छी तरह से परिभाषित रूपरेखाएं हैं, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि चोरी और हत्या के आवारा और असंगठित अपराध सार्वजनिक व्यवस्था के मामले नहीं हैं क्योंकि वे सार्वजनिक जीवन के समान प्रवाह को प्रभावित नहीं आदेशते हैं। कानून के उल्लंघन कुछ हद तक अव्यवस्था का कारण बनते हैं लेकिन कानून के हर उल्लंघन के परिणामस्वरूप सार्वजनिक अव्यवस्था नहीं होती है। कानून और व्यवस्था सबसे बड़े पैमाने का प्रतिनिधित्व आदेशता है जिसके भीतर अगला वृत्त सार्वजनिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व आदेशता है और सबसे छोटा वृत्त राज्य की सुरक्षा का प्रतिनिधित्व आदेशता है। "कानून और व्यवस्था "सार्वजनिक व्यवस्था" को प्रभावित करने वालों की तुलना में कम गंभीरता वाले विकारों को ठीक उसी तरह समझती है जैसे "सार्वजनिक व्यवस्था" "राज्य की सुरक्षा" को प्रभावित करने वालों की तुलना में

कम गंभीरता वाले विकारों को समझती है। [कुसो साह अन्य बिहार राज्य और अन्य देखें। (1974)।(1) एस. सी. सी. 185, गुरप्रीत कौर बनाम महाराष्ट्र राज्य(1992)।(2) एससीसी 177, टी. के. गोपाल बनाम कर्नाटक राज्य (2000 (6) एससीसी 168, महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद याकूब (1980 (2) एससीआर 1158) और पुलिस आयुक्त बनाम सी. अनीता (2004 (7), एससीसी 467)।-

14. लाइव लिंक के सवाल पर यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 'निरोध को सशक्त बनाने का प्रावधान प्रस्तावित बंदी की आदतन गतिविधियों से संबंधित है। इसलिए ऐसा उदाहरण होना चाहिए जो न भी हो। तत्काल निकटता का होना लेकिन उस पैटर्न को इंगित कर सकता है। उदाहरण के मामले में लाइव लिंक की अनुपस्थिति में के निष्कर्ष की गारंटी देने के लिए घटना को दूरस्थ अतीत नहीं कहा जा सकता है।

15. इसके अलावा अधिनियम की खंड 8 (2) गवाहों की पहचान को रोकने की अनुमति देती है। इसलिए हम इस अपील में कोई सार नहीं पाते हैं, जिसे तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

एनजे अपील खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।